

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 6 जनवरी 2024 शनिवार

सम्पादकीय

बढ़ते साइबर अपराध

ऑन लाइन सेवाओं के विस्तार ने हमारे जीवन को जितना सुगम व सरल बनाया है, उतना ही खतरा साइबर अपराधों का भी बढ़ा है। दरअसल, देश में साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने में देरी और लोगों में जागरूकता की कमी से भी अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। यह खबर परेशान करने वाली है कि देश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व हरियाणा में साइबर अपराध की दर सबसे ज्यादा है। बल्कि हरियाणा में मेवात साइबर अपराधों के जरिये वसूली का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यह स्थिति किसकी चिंताजनक है कि पिछले तीन साल में वित्तीय घोखाधड़ी में दस हजार तीन सौ नब्बे करोड़ रुपये का चूना लोगों को लगा। कर्मोबेश साइबर अपराधियों के सुनियोजित गिरोहों द्वारा लोगों के विश्वास के साथ छल करके खून-पसीने की कमाई पर भ्रमजाल में फंस जाते हैं और उसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं। यह समस्या कितना जटिल रूप ले चुकी है कि देश में एक लाख की आबादी पर 129 साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं। लेकिन इसकी संख्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रति लाख आबादी पर 755, चंडीगढ़ में 432 तथा हरियाणा में 381 है। इन स्थानों पर ज्यादा साइबर क्राइम होने की एक वजह यह भी है कि ऑनलाइन विकल्पों के प्रति जागरूकता के चलते अधिक लोग इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। वैसे साइबर क्राइम की छद्म प्रवृत्ति से अनभिज्ञ लोग भी जल्दी अपराधियों के झंझरे में फंस जाते हैं। हालांकि, देश की केंद्रीय एजेंसियां लगातार अपराधियों पर नजर रखे हुए हैं और निरंतर इनके खिलाफ अभियान चलाती रहती हैं। मेवात सहित कई राज्यों में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए हैं। राष्ट्रीय एजेंसियों ने 2.9 लाख फर्जी निम, 2810 गलत मंशा से चलाए जा रहे यूआरएल और 595 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए हैं। लेकिन इसके बावजूद कहना कठिन है कि साइबर क्राइम इन कार्रवाइयों से कम हुए हैं।

दरअसल, साइबर अपराधी पुलिस व जांच एजेंसियों की सक्रियता के बावजूद अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। साइबर अपराधों का दायरा इतना विस्तृत व जटिल है कि पुलिस भी उन पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकती। असल में, अपराध की दुनिया में साइबर अपराध की शुरुआत एक नया खतरा है, जिसके लिए हम अपनी पुलिस को पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं कर पाए हैं। साथ ही नागरिकों को भी इस भ्रमजाल से बचने के लिये पर्याप्त रूप से जागरूक करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर अपराध का स्वरूप देखें तो वर्ष 2023 में सभी साइबर अपराधों में 38 फीसदी घोखाधड़ी निवेश से संबंधित थी। इसके बाद ग्राहक सेवा या रिफंड लौटाने के नाम पर जरूरी जानकारी लेकर फ्राड करने अथवा केवाईसी समाप्ति संबंधी झूठी सूचना देकर ठगने के मामले प्रकाश में आए। इनमें ही नहीं सेक्टरटॉशन के जरिये भी धन वसूली के बहुत मामले प्रकाश में आए। इसमें वीडियो कॉल के जरिये लोगों के चित्र को अश्लील दृश्यों से जोड़कर बदनाम करने की धमकी देकर धन वसूला जाता है। यही वजह है कि साइबर विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अनजान वीडियो कॉल का जवाब न दें। यदि वे कॉल लेते हैं तो सेक्टरटॉशन के शिकार बन सकते हैं। दरअसल, साइबर विशेषज्ञ बैंकों के साथ काम करके उस गिरोहबंदी को रोकने पर काम कर रहे हैं जिसमें एक खाते से धन हस्तांतरित करके आगे अन्य खातों में भेज दिया जाता है और दूसरे के नाम से निकाल लिया जाता है। देश में साइबर अपराधों का वर्ष 2022 से 2023 में 61 फीसदी की दर से बढ़ना गंभीर चेतावनी है। यह बदलाव है कि इससे पहले वर्ष में यह वृद्धि एक सी तरह प्रतीत थी। यह अच्छी बात है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च होने के बाद लोगों को राहत मिली है। जिसके चलते साइबर अपराधों में 4.3 लाख नागरिकों के हुए नुकसान में से एक हजार एक सौ सत्ताईस करोड़ रुपये की वसूली की जा सकी है। लोगों को ऐप की अनुमति देते वक्त सावधान रहने की बात कही गई है।

इण्डिया गठबंधन: मायावती के फैसले पर टिकी निगाहें



—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तब तक कोई गठबंधन कामयाब नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ नजर नहीं आये। 2019 के यानी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद नंबर दो पर रही बसपा को सबसे अधिक वोट मिले थे और सपा को बसपा के मुकाबले करीब डेढ़ फीसदी कम वोट पड़े थे। बाकी दल चाहे उसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस हो या फिर परिवर्षी यूपी तक सीमित राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों दलों की इतनी ताकत नहीं है कि वह सपा-बसपा के बिना कोई बड़ा उलटफेर कर सके। वैसे इन दलों के अलावा अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल (कमेरावादी), जनता दल यूनाइटेड, आजाद समाज पार्टी, जनसत्ता दल लोकसहित एवं एआईएमआरएम जैसी पार्टियां भी हैं जिनका पिछले उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में वोट एक प्रतिशत के नीचे ही रहा था। अपना दल सोनेलाल पट्ट जो बीजेपी के साथ है, उसको जरूर डेढ़ प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। इन दलों का यही हाल कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। यह अंकड़ें उन लोगों के लिए एक संदेश हैं जो यूपी में इन दलों को साथ लेकर कोई बड़ा उलटफेर का सपना



संजोये हुए हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बल पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे गैर बीजेपी दलों के लिए 2017 के उत्तर प्रदेश विधान सभा और 2019 के लोकसभा चुनाव एक बनानी हैं। 2017 का विधान सभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन भी कुछ खास नहीं कर पाया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि समाजवादी पार्टी नेता इस हकीकत से अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्यों बसपा को साथ नहीं लेना चाहते हैं, यह रहस्य बना हुआ है। जबकि कांग्रेस खुलकर कह चुकी है कि वह इंडी गठबंधन में बसपा को भी देवना चाहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का ठीकठाक वोट बैंक है। दलितों में उनकी अच्छी खासी पेट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा-बसपा मिलकर गठबंधन लड़े थे, तब बसपा को 19.88 फीसदी वोट मिले थे, जो सपा से कुछ ज्यादा ही थे। सपा को 18.11

फीसदी मत हासिल हुए थे। बहरहाल, गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर अभी तय्यार सफा नहीं है। हालांकि गैर बीजेपी गठबंधन वाले नेता और अन्य वर्ग के लोग बसपा को इंडी गठबंधन में शामिल करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। परंतु अखिलेश अपनी बात पर अड़े हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली में गठबंधन की बैठक में भी जब इस पर बात हुई तो सपा ने आपसि जताई थी। सपा ने दो टुक कर दिया था कि सपा आगामी तो वह बाहर निकल जाएगी। अब यूपी कांग्रेस से मांग उठी है कि गठबंधन में बसपा को भी शामिल किया जाए। दरअसल, कांग्रेस पार्टी भाजपा को 2024 में शिकस्त देने के लिए अपनी तरफका के हर तीन आजमाना लेना चाहती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दलित वोटर्स में मायावती की पेट को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि मायावती साथ आई तो दलित वोट मिलना आसान हो जाएगा। यूपी में 20 प्रतिशत आबादी दलितों की है।

मायावती की चर्चा चलने लगी

करीब 15 और रोलोद को पांच से छह सीटें दिये जाने की संभावना है। सपा करीब 58 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन बसपा के गठबंधन में शामिल होने से सभी दलों की सीटों में कटौती निश्चित है। पिछले दिनों पिछा की बैठक के बाद मायावती ने सामने आकर कहा था कि मंत्रिध में देश में जनहित में सब किसको किसकी जरूरत पड़े जाए, कहा नहीं जा सकता है। दरअसल, मायावती को भी पता है कि भाजपा के जनाार को देखते हुए बसपा के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाना चुनौती होगी। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थी। अपने दम पर शायद इस बार उतनी सीटें न मिलें, ऐसे में बसपा भी चाहेगी कि वह गठबंधन में आकर अच्छा प्रदर्शन कर सके।

2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा और राष्ट्रीय लोकतल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसे करीब 40 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा को करीब 20 प्रतिशत, सपा को 19 और रोलोद को 1.69 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा के बारे में देखा गया है कि वह बहुत पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है लेकिन इस बार उसने प्रमारी भी नहीं बनाई है। बसपा के लोग मान रहे हैं कि हो सकता है कि सपा को लेकर जनदी स्थिति साफ हो। उत्तर, बसपा को इंडी गठबंधन से दूर रखने की समाजवादी कोशिश की बात की जाये तो सपा कम से कम सीटों का बंटवारा करना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जानते हैं कि जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका आधार बनेंगे और उन चुनावों में बसपा को सपा से अधिक वोट और सीटें मिली थी, जिसके चलते उसकी दावेदारी भी ज्यादा मजबूत होगी। बसपा किसी भी सूत्र में सपा से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होगी। इसीलिए अखिलेश बसपा को गठबंधन का

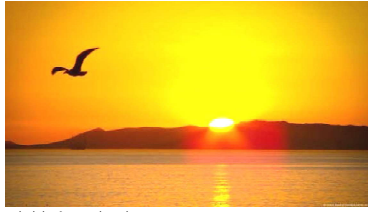
हिस्सा नहीं बनने देना चाहते हैं, इसके लिए अखिलेश यादव यहां तक कहने लगे हैं कि यदि बसपा को गठबंधन में शामिल किया गया तो वह गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। दरअसल, अखिलेश चाहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा हो, जिसके नतीजे कांग्रेस और बसपा के लिए बेहतर निराशाजनक रहे थे। 2007 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी मायावती की पार्टी को 15 साल बाद 2022 में मात्र एक विधान सभा सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी कुछ भी दलील दे, लेकिन कांग्रेस की दलील तमना यही है कि बसपा को भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाये। जो सही भी है, यदि बसपा भी इंडी एलायंस का गठबंधन का हिस्सा होती है तो यूपी में कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का समीकरण गड़बड़ा सकता है। उत्तर, सपा की बात की जाये तो उसके लिये भी राह आसान नहीं बनती है। उसके अपने ही उरुसका सपा छोड़ने को पड़े है। हालत यह है कि इंडीया गठबंधन में शामिल होकर पीएफ का झंडा धारण में लगे अखिलेश यादव से अब परंपरागत यादव वोट बैंक भी खिसक रहा है। सालों से मुलियाम सिंह यादव की सरकार में चल रही अखिल भारतीय यादव महासभा में दो फाड़ हो गयी है। यूपी में यादव तबके ने यादव बंध बना कर सपा की अलग कति की छाप से खुद को खिसक जाते हैं। यादव महासभा का सपा से भोग भोग और अखिलेश यादव के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ओबीसी कुनूने को झटका करने में जुटे अखिलेश यादव को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ये पता चला है कि 2022 के लोकसभा चुनाव में सपा से अधिक वोट और सीटें मिली थी, जिसके चलते उसकी दावेदारी भी ज्यादा मजबूत होगी। बसपा किसी भी सूत्र में सपा से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होगी। इसीलिए अखिलेश बसपा को गठबंधन का

नये साल से उम्मीदें और चुनौतियां



—ललित गर्ग—

नया साल प्रारंभ हो गया है तो हर बार की तरह इस बार भी नई उम्मीदें, नया विश्वास एवं नया प्रयास लाना है। बीत गया एक वर्ष। नये की स्वीकृति के साथ पुनर्ने को अलविदा कह देने की सामान्य सोच रही है। यह समझ देना गयी है कि नयेपन के जाउई अक्षयों के जागते ही हमन पुरानेपन को उतार फेंकना चाहते हैं। हमने बीते वर्ष में श्रेष्ठताओं की उपलब्धि पर सात्विक गर्व करने की अनेक स्थितियों को रचा है लेकिन हम सबके लिए और देश के लिए भी आने वाले वर्ष कुछ महत्वपूर्ण करणीय कार्य करने का। इन क्षम जड़कों को तोड़कर मुक्त होती है हमारे विकास की उजली संभावना। यह अच्छाईयें एवं अंधरे रहे कार्यों को पूरा करने की और मुझे की प्रेरणा है। अर्थशून्य दूर की जीवनशैली एवं विविध योजनाओं को बदलने का बुद्धिगु सुझाव है। समस्याएं जब बहुत चिन्तनयोग्य बन जाती है तो उसे बड़ी गंभीरता से नया मोड़ एवं एकाग्र देने की जरूरत है। शिक्षा, विविध एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं से



जुड़े ऐसे ही अफसोस के अहसास हमारे लिये गंभीर होना चाहिए।

आजादी के अमृत काल में भी शिक्षा, विविधता एवं पर्यावरण से जुड़ी चिन्ताओं का गहन बना रहना हमारी विकास यात्रा पर एक सवालिया निशान है। शिक्षा जागत से जुड़ी एक खबर सामने आई है, वह यह कि बन्ती महंगाई और बदलते नियमों से विदेशों में पढ़ाई मुश्किल हुई है। सच जानते हैं कि शिक्षा हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर मां-बाप अपने बच्चों को गुच्छा शिक्षा दिलाना चाहते हैं। कई बार अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश भी भेजना पड़ता है। खयाल यह है कि आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे नंबर वाला देश क्या अपने यहां ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा सकता? यह सवाल करोड़ों बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार के अंतर्गत एवं खास्य प्रवर्तनों के बावजूद शिक्षा और विविधता के लगातार महंगे होने की निता से हर कोई परेशान है। शिक्षा और विविधता को व्यवसाय बना देने पर निजी हाथों में सौंप देने से ही दोनों महंगी और दुर्लभ हो गई हैं। इसकी वजह जनसंख्या के मुताबिक उपलब्धता की कमी और व्यावसायिकता है। नये भारत के निर्माण के साथ समय की इस दरतक को सुनें। निश्चित ही यह भारत की समृद्धि एवं विश्व प्रतियोगिता की दृष्टि से एक अलग उकम हो सकता है, लेकिन प्रश्न भारतीय छात्रों का है, उनकी शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का है। महंगी

तेजी से होने लगी है। तमाम सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं को शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो देश का निम्न एवं मजदूर वर्ग यह सोचने को मजबूर है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करे। निजी कॉलेजों में तो इतना अधिक पैसा लगता है कि मध्य वर्ग के भी कान खड़े हो जाते हैं, तो फिर निम्न वर्ग की बात ही क्या?

यहां मातृ संघ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह जा रहा। शिक्षा के साथ एक और विषय है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वह है, विकसिता। जिस तरह गुणवत्ता के मामले में भारत के विश्वविद्यालयों पिछड़े हुए हैं, उसी तरह की छवि भारत के अस्पतालों की है। मतलब साफ है कि अच्छी पढ़ाई हो या बेहतर इलाज, जैसे पेसा हो तो पकड़ो वीडिओईए गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के बीच झारखंड सरकार के मंत्रियों को लेकर उल्लाहों की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस के राज्य विधायक दल ने भी आपस-फांनर में तीन जनकों को एक बैठक आहूत की, जिसमें एक के चारों मंत्रियों समेत 13 विधायक तथा राज्य कांग्रेस के प्रमारी गुलाम अहमद मीर ने भी भाग लिया। हालांकि, कांग्रेस की ओर से मीर ने बैठक को लेकर मीडिया से इतना ही कहा कि विधायकों के साथ बैठक काफी अच्छी रही।

देखा जाए तो कांग्रेस की यह बैठक टालने में अपने विधायकों की नब्ब टालने के एक कोशिश भर थी। दरअसल, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह डर सता रहा है कि कहीं संकट की घड़ी हमें उठने के लिए पकड़ न जाए। इसीलिए कांग्रेस के आलाकामन ने राज्य कांग्रेस के प्रमारी मीर को एकदम मेजबान किए मीर को एकदम मेजबान के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही गयी। इस बात में जजर इस्लाम भी है, क्योंकि बनारस में आइएएनडीआईए गठबंधन के भीतर यदि सबसे अधिक खतरा किसी पार्टी के टूटने का है तो वह कांग्रेस ही है, क्योंकि संकट की घड़ी आने पर सबसे पहले कांग्रेसी विधायक ही झू-र से—उभर होते गए गए हैं। इससे पहले भी एक बार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के गिरने की

ई.डी. और हेमंत सोरेन



—चेतनादित्य आलोचन—

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से भेजे गए समन के मद्देनजर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में यह कसरत लगाया जा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की प्थायें ही इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीतिक विरसा सौंप सकते हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सांखी बार भेजे गए समन को लेकर झारखंड यूथ मोर्चा के नेताओं समेत आइएएनडीआईए गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के बीच झारखंड सरकार के मंत्रियों को लेकर उल्लाहों की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस के राज्य विधायक दल ने भी आपस-फांनर में तीन जनकों को एक बैठक आहूत की, जिसमें एक के चारों मंत्रियों समेत 13 विधायक तथा राज्य कांग्रेस के प्रमारी गुलाम अहमद मीर ने भी भाग लिया। हालांकि, कांग्रेस की ओर से मीर ने बैठक को लेकर मीडिया से इतना ही कहा कि विधायकों के साथ बैठक काफी अच्छी रही।

देखा जाए तो कांग्रेस की यह बैठक टालने में अपने विधायकों की नब्ब टालने के एक कोशिश भर थी। दरअसल, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह डर सता रहा है कि कहीं संकट की घड़ी हमें उठने के लिए पकड़ न जाए। इसीलिए कांग्रेस के आलाकामन ने राज्य कांग्रेस के प्रमारी मीर को एकदम मेजबान किए मीर को एकदम मेजबान के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही गयी। इस बात में जजर इस्लाम भी है, क्योंकि बनारस में आइएएनडीआईए गठबंधन के भीतर यदि सबसे अधिक खतरा किसी पार्टी के टूटने का है तो वह कांग्रेस ही है, क्योंकि संकट की घड़ी आने पर सबसे पहले कांग्रेसी विधायक ही झू-र से—उभर होते गए गए हैं। इससे पहले भी एक बार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के गिरने की

खबर फैली थी, जब राजनीतिक गलियारों में यह बात खूब उछली थी कि कई कांग्रेसी विधायक भाजपा के कुछ केंद्रीय एवं स्थानीय नेताओं के संपर्क में आगताएं बने हुए हैं। उस समय कांग्रेसी विधायकों की आलाकामन से भाजपाजी उनके टूटने की वजह बताई जा रही थी। तब पार्टी को तोड़कर भाजपा में शामिल होने के कथित आरोपी विधायकों का बंगाल कनेक्शन खुलकर सामने आया था। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड सरकार पर आने वाले संकट को माफकर पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ली उनका बाहता था।

लेना बाहता में भीतर ईडी की ओर से मुख्यमंत्री सोरेन को भेजे गए समन के लेकर अलग तरीका का मास्की बना हुआ है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी की ओर से उनके सातवीं बार समन भेजा गया था, जिसे आखिरी समन बाहता जा रहा है। हालांकि उत्तर बाहता का हिस्सा बनाते हुए मुख्यमंत्री इस बार भी ईडी के सख्त उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने समन का गोलाम गोलाम जवाब भेज दिया। देखा जाए तो ईडी को जवाब सज्जर उन्होंने खानामूर्ति भले ही कर ली हो, लेकिन वे भी जानते हैं कि उनके ऊपर ईडी की तलवार हर वक्त लटक रही है, जिससे अब उनका बचना बेदरकार नहीं है। बल्कि अरुमन प्रतीति होने लगा है। प्रमुख कारण इस मामले में ईडी का वह अल्टीमेटम है, जो एजेंसी ने मुख्यमंत्री को समन के साथ भेजा था। उसमें एजेंसी ने मुख्यमंत्री से साफ-साफ कहा था कि यदि आप तो पृष्ठछाट के लिए वे स्वयं उपस्थित हों अथवा कहीं एजेंसी को स्थान और स्थिति बाहता ताकि उनसे पृष्ठछाट की जा सके। बहरहाल, अब इस मामले में यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी के विचार प्रतियोग अपनावकर पृष्ठछाट करने के लिए मुख्यमंत्री को विरसा में ले सकती है। संभव है कि विषय के नेता हेमंत सोरेन से इस कदम को मूर्खतापूर्ण मानने की गलती कर दें, लेकिन सच यह है कि गिरफ्तारी अथवा ईडी द्वारा विरसा में लिए जाने की स्थिति में सोरेन जनता के बीच की रूढ़ि को पीछे (विचित्र) दिखाकर आगे की राजनीतिक गति की तैयारी में हैं।

एक मुक्तिक के बंद गाँव राँचेर खोजीन।
 पत्नी की लहरीयें पर अस्तात बालक
 के खिलार एफ़ाईआर दर्ज कर
 रही हैं।

पत्नी के बच्चों का रो-रोकर हास
 बेहोशलेर बताया जाता है कि सम्पन्न
 घर से से ड्राइव था। उसकी गाड़ी
 खराब थी जिसकी मरम्मत के लिए दो
 सप्ताह तक गाड़ी सड़क के किनारे हो गयी।
 माँसहारे के बाद पति प्रिकार हो गया।
 कालांतर के बाद पति का शरीर
 काकाएल, अरुण, आंखल व रोनीनी
 का रो-रोकर बताव बेवहार है।
 माँसहारे के बाद दुर्गुमो बच्चे को देखकर
 दहाइदाइ माँकर रो रही है।

आरोप में नपे एक्सईएन

हालातों का ठग से सम्भन भी नहीं
 सके थे। इसी वीर पर पत्नी का
 कर दिव जाने से हतिमन के अतिव्यय
 य कमी भी सम्भन में है। जल जियन
 के कारण के सहित हर घर खुद भुयल
 महुदुनेन को कायनाओं को दूत कर
 महुदुनेन में दो बड़ी योजनयाँ लगी हुई है।

हालातों इन्ने 135 पत्नी टरिफ़ो
 के निमण पर गाँव-गाँव पाइल लागन
 का कार्य भी तेजी से करिया
 जा रहा है। बताया जा रहा है ककिया
 एक्सईएन को इमरान अरुण
 एक्सईएनयोजनाओं के कार्यों व शह के
 हालातों को भी समझ रहे थे। जिले
 व नईन शहर की बन्दूक में अक्सर
 ये मातहत अभियंताओं को साथ ले
 जाते हैं। बताया है कि कुवारा को विमान
 के मण्डल सप्लाय करवाकर सिंह की
 काल के दौरान उन पर कफ़ीयों
 की ओर से गमीर आरोप मढ़े थे। जिले
 के जजिक के बाद एक्सईएन के विवाद
 खत्म हो चुकी हैं।

